प्र.1 - भारत-बांग्लादेश संबंधों की प्रगाढ़ता की राह में 'तीस्ता नदी जल विवाद' एक बड़ा अवरोधक रहा है। अगर इस नदी जल विवाद की समस्या का समाधान हो जाए तो दोनों देशों को क्या-क्या लाभ की संभावनाएँ है? परीक्षण कीजिए। (200 शब्द)

मॉडल उत्तर

दृष्टिकोण:

- भूमिका में भारत-बांग्लादेश संबंधों की चर्चा करते हुये बतायें की 'तीस्ता नदी जल विवाद' एक बड़ा अवरोधक क्यों रहा है?
- इस नदी जल विवाद की समस्या का समाधान हो जाए तो दोनों देशों को क्या-क्या लाभ की संभावनाएँ है?
- अंत में संतुलित निष्कर्ष दें।

बांग्लादेश को आजाद कराने में सबसे अहम योगदान देने के बावजूद भारत के संबंध बांग्लादेश के साथ प्रगाढ़ता के उस स्तर तक नहीं पहुँच पाये हैं जिस स्तर पर दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे पर आँख मूंदकर भरोसा किया जा सके। वर्तमान में **'तीस्ता नदी जल विवाद'** दोनों देशों के मध्य संबंधों की प्रगाढ़ता में एक बड़ा अवरोध रहा है।

1983 में तीस्ता के पानी के बँटवारे पर एक तदर्थ समझौता हुआ था जिसके तहत बांग्लादेश को नदी जल का 36 प्रतिशत तथा भारत को 39 प्रतिशत पानी के इस्तेमाल का हक मिला। बाकी 25 प्रतिशत पानी का आवंटन नहीं किया गया। 2013 में मनमोहन सिंह तथा शेख हसीना के बीच समझौता हुआ। जानकारों के अनुसार नए समझौते के प्रारूप में बांग्लादेश को नदी जल का 48 फीसदी पानी मिलना था, किन्तु प. बंगाल सरकार के अनुसार इससे राज्य के 6 उत्तरी जिलों की सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो जाती। इसलिए यह समझौता मंजूर नहीं हो पाया है।

इस नदी जल विवाद की समस्या का समाधान हो जाए तो दोनों देशों को निम्न लाभ की संभवनाए है-

- पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ऐतिहासिक सांस्कृति व भाषायी एकरूपता है, अतः नदी जल विवाद की समस्या का समाधान होने से सहयोग बढ़ेगा और अन्य समझौतों के लिए आधार तैयार होगा।
- बांग्लादेश के उत्तरी भाग में चावल, पटसन, जूट, चाय आदि की खेती होती है, जिसे उचित जल मिलेगा सूखे की समस्या का समाधान होगा।
- शरणार्थी, अवैध घुसपैठ की समस्या कम होगी और अन्य मुद्दों (आतंकवाद, उग्रवाद) पर भी बांग्लादेश सहयोग दे सकता है।
- इस समझौते से भारत को बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने हेतु रणनीतिक लाभ की स्थिति प्राप्त होगी।